REVIEW OF RESEARCH
IMPACT FACTOR : 5.7631(UIF) UGC APPROVED JOURNAL NO. 48514 ISSN: 2249-894X
VOLUME - 8 | ISSUE - 6 | MARCH - 2019

विमुद्रीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था – एक अध्ययन

डॉ. असलम सईद
विभागाध्यक्ष वाणिज्य , ए.के.एस.वि.वि.सतना.

सारांश

किसी भी स्वस्थ अर्थव्यवस्था के लिए, वैद्य मुद्रा का प्रवाह सुनिश्चित करना आवश्यक है, ताकि इसका उपयोग नागरिकों द्वारा उनकी विविध दैनंदिन गतिविधियों के लिए किया जा सके। जैसे– जैसे साक्षरता और शिक्षा का स्तर बढ़ता जाता है, वैसे – वैसे अधिकांश नागरिक ऑनलाइन या प्लास्टिक लेनदेनों की ओर बढ़ सकते है जैसा कि हमने यूराप और अन्यत्र देशों में देखा है वास्तव में सपूर्ण मौद्रिक व्यवस्था में चलनगत मुद्रा का हिस्सा बहुत ही अल्प होता है, परंतु एक सामान्य नागरिक के लिए यह एक सुचारू दैनंदिन जीवन के लिए महत्वपूर्ण होता है।

भारत जैसे विकासशील देशों में जहाँ बड़े पैमाने पर विविध निकायों के लिए नियमित रूप से होने वाले चुनावों के ईमानदार, और पारदर्शी वित्तपोषण जैसे प्रमुख मुद्दों पर कोई ठोस उपाय नहीं किये गए हैं, वहां बड़े करेंसी नोट स्वरूप में धन भ्रष्टाचार का सुव्यवस्थित और संस्थागत मार्ग होता है, जो संपूर्ण व्यवस्था को जड़ से खोंखला कर देता है। इसकी विशालता और नियमितता के कारण यह सरकार के अंदर और दैनंदिन जीवन में शून्य – भृष्टाचर के अधिकांश अन्य उपायो को एक मजाक बना देता है। और चुनाव के वित्तपोषण में भ्रष्टाचार के विशाल द्वार खुले होने कारण अन्य बुराइयों भी प्रवेश करती हैं जैसे कर अपवंचन , वित्तीय अपराध, आतंकवाद का वित्तपोषण, मादक पदार्थो का व्यापार, अंडरवर्ल्ड गतिविधियाँ और अन्य।

सामाजिक मीडिया के माध्यम से ऑनलाइन जागरूकता और वर्ष 2005 के बाद संचार मीडिया के प्रसार के साथ अधिकांश भारतीय नागरिक, पारदर्शी शासन और उच्च गुणवत्ता का जीवन प्रदान करने के लिए निर्माण किये गए लगभग सभी संस्थागत तंत्रों की भारी गिरावट में बारीकी से वाकिफ हो गए है। राजरनीतिक भ्रष्टाचार के माध्यम से मौद्रिक अवसरो को झपटने की प्रवृत्ति पर क्रोध काफी बढ़ा है। अब भारतीय नागरिक अपने राजनीतिज्ञों को अपार धन एकत्रित करते हुए चुपचाप देखते रहना चाहते हैं, अनेकानेक न्यायालयीन निर्णय और आम आदमी पार्टी जैसी राजनीतिक विचारोधारों का जन्म इसके प्रमाण हैं। दुर्भाग्य से, इस विषय पर होने है, यह कोई स्वस्थ संकेत नहीं है। अतः काले धन को समाप्त करना एक राजनीतिक मुद्दा बन गया है, और किसी भी नेता के लिए जो इस समाप्त कर देने हेतु प्रतिबद्ध दिखे, उसे बड़ा चुनावी इनाम मिलना तय है। और एक आधुनिकता का लबादा भी है – कैशलेश बनें, डिजिटल बनें , आधुनिक कहलाएं।

वास्तव में धन (पैसा) ही एक जटिल समाज में रहने वाले लोगों के एक – दूसरों पर विश्वास की अभिव्यक्ति और कानून के राज के प्रति आस्था का परिचायक है। यह कायम करता है कि पैसा ही मूल्य का सामान्य संग्रह है, विनिमय का साधन है, और मापन का पैमाना है। पैसा, सब कुछ एक समान पैमाने पर लाकर अन्य बातों को आसान बना देता है। दार्शनिकों ने तो कहा भी है कि पैसा ही सभी बुराइयों की जड़ है कोई भी वित्तीय लेनदेन जो कर अपवचंन के उद्देश से अधिकारियों की परिधि से बाहर रखा गया है काला धन कहलाता है। इसका उपयोग केवल अधिक बचत के उद्देश्य से अपनी आय को छिपाना हो सकता है, या आतंकवाद, मानव तस्करी मादक पदार्थो की तस्करी , भ्रष्टाचार और वित्तीय अपराधों के लिए किया जा सकता है। ये ही वे कारण हैं जो काले धन को खतरनाक बनाते हैं, और सबसे भ्रष्ट राजनेता भी इस बहुमुखी दानव का ये चेहरा पहचानता है। काला धन अनैतिक हो सकता है(सही तरीकों से कमाया गया पर सरकार से छुपाया गया) या फिर मलिन (गन्दा) हो सकता है (अपराधों से कमाया गया) ध्यान रहे कि बहुत सा 'काला' धन अनैतिक न होते हुए आवश्यकता – आधारित होता है जैसा कि भारत भर की माताओं और पत्नियों के द्वारा एकत्रित नगदी के सूक्ष्म भण्डार सिद्ध करते है।

विमुद्रीकरण वह कानूनी प्रक्रिया है जिससे मौजूद किसी करेंसी नोट को अमान्य घोषित, उसी मूल्य के अथवा भिन्न के नोटों से प्रतिस्थापित किया जाता है। ये एक शॉक थेरेपी (झटके से किया इलाज) होती है जिसका लक्ष्य होता है अवैध मुद्रा का विनाश (जो वैद्य संपत्ति नही होती), और ईमानदार करदाता नागरिकों के भरोसे का पुनर्प्रतिस्थापन। भारत मे विमुद्रीकरण का अनुभव 1946 में, फिर 1978 में और फिर 2016 में

लिया है। किन्तु आज के 132 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले भारत में हुए विमुद्रीकरण के तुरंत बाद की स्थिति में स्पष्ट है कि एटीएम ऑपरेशन्य को योजनाबद्ध ढंग से प्रबंधित नहीं किया गया। किन्तु असली खतरा ये भी नहीं है – वो तो तब उभरेगा जब ये नए – जन्मे करोड़ों करदाता सफेद अर्थव्यवस्था का अचानक से हिस्सा बनेंगे – अपनी गाढ़ी खून – पशीने की कमाई से कर अदा करने के बाद – और फिर है सभी सरकारी मंत्रालयो और विभागों से केंद्रीय और राज्य स्तरीय, अच्छी सेवाओं की अपेक्षा लगा बैठेंगे।

भारत सहित अधिकांश देशों में नगदी का महत्व कम हो रहा है, परंतु यह अत्यंत धीमी गति से हो रहा है और एक विशिष्ट आय के स्तर के नीचे रहने वाले अधिकांश भारतीयों के लिए ऐसा नहीं हो रहा है, और निम्न या माध्यम आय समाज में रहने वाली महिलाओं के लिए तो ऐसा निश्चित रूप से नहीं हो रहा है।

प्रस्तावनाः–

किसी देश के द्वारा जब देश में प्रचलित मुद्रा को किसी विशेष कारण से कानूनी रूप देकर अवैध घोषित कर दिया जाता है और उस मुद्रा के स्थान पर नयी मुद्रा को प्रचलन मे ले आया जाता है, इसके साथ – साथ पुरानी अवैघ मुद्रा को नई वैद्य मुद्रा से बदलने का एक समय निश्चित कर दिया जाता है तो उसे विमुद्रीकरण कहते है।

वास्तव में विमुद्रीकरण वह स्थिती है जहाँ किसी देश की सरकार के द्वारा वड़े मूल्यो की नोटो को बद करके उनके चलन पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। इस प्रतिबंध के लगने के पश्चात इन नोटो से कोई लेन देन नही किया जा सकता, ना ही कुछ खरीदा जा सकता है तात्पर्य वें किसी काम के नही रहते, ऐसी पुरानी मुद्रा जिस पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है वो मात्र कागज का टुकड़ा बन कर रह जाती है।

भारत में अभी तक तीन बार पूर्ण रूप से विमुद्रीकरण किया गया है सर्वप्रथम 1946 में 500, 1000 एवं 10000 के नोटों को बंद किया गया है इसके बाद सन्1978 में मोरारजी देसाई की जनता पार्टी सरकार ने 1000, 5000, 10000 के नोट बंद कर दिये थे।

वर्तमान में 8 नवंम्बर 2016 को भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 500 एवं 1000 के नोट बंद कर दिया और सरकार ने इसके बदले में 500 एवं 2000 के नऐ नोट जारी किये।

भारत में ऐसा कदम पहली बार उठाया गया जब प्रचलित मुद्रा का 86 प्रतिशत भाग 8.11.2016 को रात 12 बजे अवैध घोषित कर दिया गया।

भारत में विमुद्रीकरण का इतिहास : –

8 नवम्बर 2016 को भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने टेलीविजन व रेडियों के माध्यम से भारत की जनता को संबोधित करते हुए कहा की 8 नवम्बर की मध्य के रात्रि 12 बजे से 500 से 1000 रूपये के नोट वैद्य नहीं मानें जायेंगे तथा पुराने नोटो को नए नोंटो से बदलने के लिए लोगो को 30 दिसम्बर तक का समय दिया गया। 500 व 1000 के नोट बंद होने के साथ ही साथ 500 व 2000 रूपये के नए नोट भी जारी किये गए जो की बैंको व एटीएम के माध्यम से लोगों को उपलब्ध हो रहे थे तथा पुराने नोटों को बैकों व डाकघरों में जमा करने की कवायद भी शुरू हो गई। ऐसा नहीं है कि विमुद्रीकरण भारत में पहली बार हुआ है, इससे पहले भी दो बार विमुद्रीकरण भारत में हो चुका है, परन्तु 2016का विमुद्रीकरण अब तक का सबसे बड़ा बदलाव है क्योंकि तकरीबन 95ः लोगो के बैक में खाते है तथा उन सभी के पास बैक से दिए गए एटीएम व डेबिट कार्ड से निकली जाने वाली 50ः से 90ः की राशि 500 व 1000 रूपये के नोट से मिलती है इन आंकड़ों के अनुसार हम यह कह सकते है कि यदि हम एटीएम कार्ड का प्रयोग करते है तो 500 व 1000की राशि की नोट का होना आवश्यक है यही वजह है कि यह अब तक का सबसे बड़ा सराहनीय व कठिन प्रयास है।

1938ः मे गठित भारतीय रिजर्व बैंक ने अभी तक 10000 से अधिक का नोट जारी नही किया है।

12 जनवरी 1946ः– भारत देश आजाद नहीं था तथा भारत में ब्रिटिश सरकार थी। उस समय ब्रिटिश सरकार ने 500 , 100 व 10000 रूपये के नोटो को बंद किया था। इस अचानक हुई नोट बंदी में लोगों का 60 – 70ः तक का नुकसान हुआ अर्थात् नोटो को बदलने पर का 60ः से 70ः तक की ही राशि प्राप्त होती थी।

1954ः– भारत आजाद हो चुका था तथा 1000, 5000 व 10000 रूपये के नोट पुनः शुरू किय गए।

1970ः– में गठित वांचू कमेटी ने प्रत्यक्ष कर की जांच करने व काले धन को बाहर के लिए सरकार को विमुद्रीकरण करने की सलाह दी थी, परंतु योजना का खुलासा होने के कारन योजना का रद्द करना पड़ा।

1977: मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता दल की सरकार बनी ।

16 जनवरी 1978:– में मोरारजी देसाई ने 1000, 5000 व 10000 मूल्य के नोटो। का विमुद्रीकरण कर दिया गया परंतु भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर आई जी पटेल ने इस फैसले का समर्थन नहीं किया।

2005:– में मनमोहन सिंह जी ने 2005 से पहले के 500 रूपये के नोटों का विमुद्रीकरण किया।

8 नवम्बर 2016:– तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनी जिन्होंने 500 व 1000 रूपये के नोटों का विमुद्रीकरण किया, परंतु इस बार भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर उर्जित पटेल ने इस फैसले का समर्थन करते हुए इसे एक साहसी कदम बताया है जबकि भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन काले धन को बाहर लाने के लिए विमुद्रीकरण को ज्यादा सफल नही मानते है।

अन्य देशों में विमुद्रीकरण का इतिहास :

- **घाना 1982 :–** नोट बंदी का कदम सबसे पहले अफ्रीकी देश घाना में उठाया गया था टेक्स चोरी और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए 50 सेडी की नोटो को बंद कर दिया गया था जनता का विश्वास अपनी मुद्रा में कम होने के कारण उन्होने जमीन जायदाद व विदेशी मुद्रा का रूख किया जिससे की बैंकिग सिस्टम को भारी नुकसान पहुँचा व काला बाजारी बढ़ गयी।
- **नाईजीरिया 1984:–** मोहम्मद बुहारी के नेतृत्व में भृष्टाचार से लड़ने के उद्देश्य से नोटों को अलग रंग में जारी किया गया था तथा पुराने नोटों को बदलने की निश्चित समय सीमा निर्धारित थी परंतु नाईजीरिया सरकार का यह फैसला पूरी तरह नाकाम साबित हुआ जिसके चलते बुहारी को अगले ही साल सत्ता से बेदखल होना पड़ा था।
- **म्यांमार 1987:–** काला बाजार को काबू में करने के लिए सत्ता सीन सरकार ने 80 फीसदी मुद्रा को अवैध घोषित कर दिया जिसका देश भर में काफी लम्बे समय तक विरोध किया गया जिनके चलते सरकार को मैन्य कार्यवाही व पुलिस का सहारा लेना पढ़ा।
- **जायरे 1990 :–** जायरे के तानाशाह मोबुतु सेसे सेको ने 1993 में अप्रचलित मुद्रा को पूरी तरह सिस्टम से वापस निकाल लेने की योजना बनायी जिसके चलते महंगाई का बढ़ना व स्थानीय मुद्रा में भारी गिरावट दर्ज की गयी इसके बाद गृह युद्ध हुआ और 1997 में मोबुतु सेसे सेको को सत्ता से बेदखल कर दिया गया।
- **सोवियत संघ 1991 :–** काली अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण पाने के लिए मिखाईल गोर्बाचेव के नेतृत्व में अंतिम साल की शुरूआत में 50 और 100 के नोटों का विमुद्रीकरण किया गया इस कदम से लोगों का सरकार की ओर से विश्वास तथा वर्चस्व दोनों कम हो गए जो की सोवियत संघ के विघटन का कारण बना।
- **रूस 1998:–** रूस ने नोटों को पूरी तरह बंद करने के स्थान पर उनका मूल्य एक हजार गुना कम कर दिया तुलनात्मक रूप से सरकार का यह फैसला आराम से निपट गया।
- **उत्तरी कोरि**या 2010 :– अर्थव्यवस्था पर काबू पाने व कालाबाजारी को कम करने के लिए उत्तर कोरिया के तानाशाह कमि जोंग इल ने पुरानी करेंसी से दो शून्य हटा दिया जिससे 100 का नोट एक का रह गया। कृषि संकट खाद्यान संकट, जनता ाक आक्रोश चावल की बढ़ती कीमतों आदि के चलते कमी को क्षमा याचना करनी पड़ी व इसी वजह से तत्कालीन वित प्रमुख को फांसी दे दी गयी थी।

विमुद्रीकरण के कारण एंव भारत में विमुद्रीकरण की आवश्यकता:–

कारण : – विमुद्रीकरण मुख्यतः निम्न कारणों से किया जाता है।

1. कालाधन (ठसंबा उवदमल) पर अंकुश लगाने के उद्देश से ।
2. भ्रष्टाचार (ब्वततनचजपवद) रोकने के उद्देश्य से ।
3. नकली नोट और आतंकी गतिविधीयों पर अकुंश लगाने के उद्देश्य से ।
4. नगद व्यवहारो का अत्याधिक प्रचलन रोकने एवं नगद लेनदेन से प्रभावित करने के उद्देश्य से।

विमुद्रीकरण के कारणों में सबसे प्रमुख कारण देश की अर्थ व्यवस्था में कालेधन और जाली मुद्रा की विनाशकारी भूमिका है जो जमाखोरी को बढ़ाती है, और यही जमा खोरी धीरे – धीरे कालेधन के रूप में इस देश में समानांतर अर्थव्यवस्था के तौर पर खड़ी हो जाती हैं, ऐसी दशा में कालाधन देश की अर्थव्यवस्था की मुख्यधारा से बाहर हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुँचता है और ये देश की सुरक्षा के लिये चुनौती बन जाता है यह कालाधन ही देश में आंतकवाद, नक्सलवाद ; अपराध, हवाला कारोबार और तस्करी का मुख्य पोषक बन जाता है।

भारत में विमुद्रीकरण की आवश्यकताः– मोदी सरकार के द्वारा सत्ता में आने के बाद "विमुद्रीकरण" का अहम फैसला लिया गया। इसकी आवश्यकता देश में बढ़ते हुऐ कालेधन की जमाखोरी और जाली नोटों के प्रचलन को समाप्त करने के लिये पड़ी।

लोंगो के द्वारा कर की चोरी के उद्देश्य के नकद लेन देन का प्रचलन बढ़ा दिया गया और इस नगद लेनदेन में बड़े नोटों का प्रयोग अधिक होने लगा, इसके साथ बहुत से जाली नोट भी बाजार में आ गये थे जो कि हमारी अर्थव्यवस्था को दीमक की तरह चाट रहे थे और अर्थव्यवस्था को खराब कर रहे थे। देश की इस बिगड़ती हुई अर्थव्यवस्था को सुनिश्चित रखने के लिये भी विमुद्रीकरण की आवश्यकता पड़ी।

विमुद्रीकरण का प्रभावः– भारतीय रिजर्व बैंक के आँकड़ों के अनुसार 31.3.2016 तक भारत में 16.42 लाख करोड़ रूपये के मूल्य के नोट बाजार में थे जिसमें से 14.18 लाख करोड़ रूपये के 500 और 1000 रूपये के नोटो के रूप में थे, इन 500 और 1000 मूल्यवर्ग के नोटो में से केवल 24 प्रतिशत भाग जनता के पास है या उनके मध्य है शेष 76ः भाग काले धन के रूप में लोगों के पास है।

ऐसे जमा कालेधन को लोगो की तिजोरी में से बाहर निकालने के लिये विमुद्रीकरण करने के निर्णय को जन्म देता है।

जब देश में विमुद्रीकरण हुआ तो इसके बहुत से प्रभाव देश के अलग – अलग क्षेत्रो में पड़े । सबसे पहला प्रभाव तो ये पडा कि विमुद्रीकरण लागू होने के अगले दिन से लोगों की भीड़ बैकों में पैसा जमा करने के लिये लगने लगी, कालाधन रखने वालों के द्वारा 500 और 1000 के नोटों को कहीं कूड़े – कचरे में फेका जाने लगा, कही उन्हे जलाये जाने का समाचार प्राप्त होने लगा। बहुत सी कम्पनियों ने जिन्होंने कई माह से मजदूरों को परिश्रामिक नही दिया था उन्होने बकाया राशि के साथ – साथ अगले कई महीनों की मजदूरी को एडवांस में चुका दिया, अर्थव्यवस्था से अचानक नकदी गायब हो गई परिणाम स्वरूप कालेधन वालो को जबरदस्त हानि उठानी पड़ी, नकली नोटों के गिरोह को चलाने वाले को आत्महत्या करने पर मजबूर होना पड़ा इसके अलावा अन्य प्रकार के प्रभाव निम्न हैः–

विमुद्रीकरण का व्यवसाय पर प्रभाव :– व्यवसाय किसी अर्थव्यवस्था की नींच है ऐसा महसूस किया गया कि विमुद्रीकरण का व्यवसायिक फर्मो पर अच्छा खासा प्रभाव पड़ा है, विमुद्रीकरण ने बड़े उद्योंगो के मुकबले छोटे उद्योगो को अधिक प्रभावित किया है क्योंकि छोटे व्यवसाय का लेन देन नगद पर ज्यादा निर्भर करता है, और मुद्रीकरण नगदी लेनदेन को प्रभावित करता है।

विमुद्रीकरण का थोक बाजार पर प्रभावः– नगद प्रवाह की कमी के कारण थोक बाजार पर का बुरा प्रभाव पड़ा, चूंकि विमुद्रीकरण के प्रभाव में 500 और 1000 मूल्य वर्ग के नोटों के बंद हो जाने से कच्चे माल की आपूर्ति सही ढंग से नही हो पा रही थी इस कारण छोटे और माध्यम आकार के व्यवसाय कम उपभोक्ता मांग कम आपूर्ति और लंबित वेतन से निपटने के लिये संघर्ष कर रहे थे।

विमुद्रीकरण का फुटकर बाजार पर प्रभावः– विमुद्रीकरण का सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र फुटकर बाजार रहा, क्योंकि 88ः लोगो ने एक सर्वेक्षण में बताया कि नगद संकट से उनकी वस्तुओं के मांग में कमी आयी तथा ग्राहकी में कमी होने से उनकी वस्तुओ के मांग मे कमी होने से विक्रय ये गिरावट आई है इस प्रकार विमुद्रीकरण का प्रभाव छोटे व्यापारियों और खुदरा बिक्री करने वालों पर अपेक्षाकृत अधिक था।

विमुद्रीकरण का रियल स्टेट क्षेत्र पर प्रभावः– वास्तव में विमुद्रीकरण का सबसे बड़ा प्रभाव रियल स्टेट क्षेत्र पर ही पड़ा क्योंकि यही एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ सबसे ज्यादा लेनदेन नगदी में होता है, विमुद्रीकरण का प्रभाव इस क्षेत्र में बहुत ही जल्दी दिखने लगा था, विमुद्रीकरण के कारण सम्पत्तियों के मूल्य में गिरावट होना इस क्षेत्र के लिये नकारात्मक प्रभाव को दर्शाता है।

विमुद्रीकरण का अंसगठित क्षेत्र पर प्रभावः – बुनियादी स्तर के श्रम भुगतान के लिये नगदी की जरूरत पड़ती है, नगदी की कमी ने असंगठित क्षेत्र को प्रभावित किया।

विमुद्रीकरण का ऑटोमोबाइल क्षेत्र पर प्रभावः – विमुद्रीकरण ने ऑटोमोबाइल क्षेत्र को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया है नगदी वो कमी के कारण चार पहिये की तुलना में दो पहिए को माँग में कमी पाई गई और क्षेत्र में बिक्री में अचानक कमी देखी गई।

विमुद्रीकरण (नोटबंदी) के लाभः– सरकार द्वारा किये गये विमुद्रीकरण के फैसले ने देश को कमजोर कर रहे सभी कारणों पर करारा प्रहार किया है यद्पि विमुद्रीकरण के समय लोगों की कुछ परेशानीयों, एवं कठिनाईयों का सामना करना पड़ा लेकिन इससे बहुत सारे लाभ भी हुये है जिसको निम्न बिंदुओ से समझा जा सकता है।

1. **कालेधन पर करारा प्रहारः–** विमुद्रीकरण का सबसे करारा चोट काले धन के कुबेरों पर पड़ा है , अनुमान लगाया गया था कि देश में लगभग गया था कि देश मे ंलगभग 3 लाख करोड़ रूपये काले धन के रूप में छिपा कर रख गए है, इन रूपयों को हवाला कारोबार, तस्करी, आतंकवाद, और आपराधिक गतिविधियो में धड़ल्ले से उपयोग हो रहा था, कश्मीर में जारी हिंसा में भी काला धन मुख्य भूमिका निभा रहा था, देश की सियासत में भी काला धन लंबे समय से एक मुद्दा रहा है, अंततः विमुद्रीकरण कर जब इस पर प्रहार किया गया, तो माना जा रहा है कि काले धन पर पूर्ण तो नहीं परन्तु इसके सम्राज्य पर लगभग 80 – 90 फीसदी प्रभाव अवश्य पड़ेगा।
2. **आतंकवाद, नक्सलवाद और आपराधिक गतिविधियों पर चोटः–** विमुद्रीकरण के चोट से आतंकवादी गुटों, नक्सली समूहों, नशे के कारोबारियों सहित अन्य गैरकानूनी गतिविधियों को करारा आघात पहुंचा है, इसका स्पष्ट प्रभाव कश्मीर में देखने को मिल रहा है एक तरफ जहाँ इन समूहों द्वारा जमा किए गए नोटों के बंडल कागज के टुकड़ों में तब्दील हो गए है ं वही नए नोटों के अभाव में इनकी गतिविधियां ठप्प पड़ गई।
3. **कर संग्रह में वृद्धिः–** सरकार ने विमुद्रीकरण से पहले और विमुद्रीकरण के दौरान काले धन को छिपाकर रखने वालों को राहत देते हुए कहा था कि वे अपने धन का खुलासा कर नियम के अनुसार टैक्स चुका कर मुख्यधारा में आ सकते हैं, इसका असर हुआ बहुत सारे लोगों ने राहत का फायदा उठाया और जो छिपे रहे उनमें से कईयों के ठिकाने पर ऐजंसियों से छापा मारकर उन्हें पकड़ा और नगदी को जब्त किया अब तक की सरकारी रिपोर्ट के अनुसार विमुद्रीकरण के बाद टैक्स कलेक्शन में 14.5 फीसदी की बढ़ोत्तरी हो चुकी है।
4. **अर्थव्यवस्था में वृद्धिः–** विमुद्रीकरण के बाद अनुमान लगाया गया है कि इस कदम से सरकारी खाते में लगभग 3 लाख करोड़ रूपये आंएगे साथ ही 65 हजार करोड़ रूपये विभिन्न करो के माध्यम से भी आने की उम्मीद है, उल्लेखनीय है कि ये आंकड़े अभी अनुमानित है ये अनुमान से कहीं अधिक भी हो सकते है, इतनी भारी भरकम आने से सरकार आधारभूत ढांचे में निवेश करेगी, जिससे देश की आर्थिक वृद्धि की रफ्तार मिलेगा।
5. **ब्याज दर में कमीः–** विमुद्रीकरण के बाद काले धन के एक बड़े भाग अर्थव्यवस्था की मुख्यधारा में आने से बैकों में डिपाजिट बढ़ेगे, बैंकों के पास पर्याप्त मात्रा में नगदी आने से वे कर्ज का प्रवाह बढ़ाएगे कर्ज का प्रवाह बढ़ाने के लिए बैंकों के लिए लाजमी हो जाएगा कि वे कर्ज पर ब्याज दर में कटौती करे, ऐसा होने पर जहां व्यावसायिक गतिविधियों में तेजी आएगी, वही पिछले दो सालों से मंदी की मार झेल रहे रियल स्टेट सेक्टर में उछाल आएगा, परिणामस्वरूप मकानों की बिक्री बढ़ने के साथ सस्ते घर का भी सपना पूरा होने की उम्मीद है।
6. **लोक कल्याणकारी योजनाओं पर खर्चः–** विमुद्रीकरण के बाद सरकार के हिस्से में आए रकम से सरकार लोक कल्याणकारी योजनाओं का दायराबढ़ायगी और पहले से चल रही योजनाओं के बजट में भी वृद्धि कर सकेगी, सरकार ने इसके संकेत भी दे दिए हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिस प्रकार मकानों के निर्माण के तय लक्ष्य और कम ब्याज के साथ मकान निर्माण के लिए दिए जाने वाले आर्थिक सहायता को बढ़ाया गया है उससे सरकार की भविष्य के प्रति मंशा स्पष्ट होती है।
7. **रोजगार में वृद्धि :–** विमुद्रीकरण के बाद सरकार के मुद्रा योजना को बल मिलेगा, नरेन्द्र मोदी सरकार के इस महत्वाकांक्षी योजना को बैंकों से अभी पूरा सहयोग नहीं मिल रहा था इसकी वजह थी बैकों के पास नगदी का संकट परन्तु अब जब बैकों में नगदी का प्रवाह बढ़ा है तो बैंक व्यावसायिक गतिविधियों में ऋण का प्रवाह बढ़ाएगें, इससे औद्योगिक गतिविधियां बढ़ेगी और परिणामस्वरूप रोजगार सृजन में बढ़ोत्तरी होगी।
8. **कैशलेस अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ते कदमः–** विमुद्रीकरण के दौरान कैश की किल्लत ने देश के लोगों को एक बड़ा सबक दिया और वह थ कैशलैस पेमेंट की मजबूरी आज वही मजबूरी देश में लोगों के सर चढ़कर बोल रहा है, कल तक जो पेमेंट लोग कैश में देना चाहते थे आज वही लोग डिजिटल पेमेंट की वकालत कर रहे है, देश में अगर यह ट्रेंड जोर पकड़ता है तो यहां आईटी सेक्टर को जबरदस्त फायदा होगा दूसरी तरफ कैशलेस अर्थव्यवस्था में काले धन की संभावनाओं पर भी काफी हद तक नियंत्रण पाया जा सकेगा।

विमुद्रीकरण से हुई हानियांः– ऐसा नही है कि विमुद्रीकरण से केवल फायदे ही फायदे हुये है, फायदे के साथ इसके नुकसान भी थे,

(1) स्थानीय पैसा न होने की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान पर्यटन स्थलों को हुआ, वास्तव में विमुद्रीकण के दौर में पर्यटन उद्योग को बड़ा धक्का लगा उस दौर में देश में स्थानीय मुद्रा की कमी से विदेशी पर्यटको को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा समस्या को देखते हुये बहुत से पर्यटक जो भारत आना चाहते है उन्होंने अपना भारत दौरा रद्द कर दिया था। इसका परिणाम यह हुआ कि देश का पर्यटन उद्योग मंदी की चपेट में आ गये , काम काज में भी बहुत मंदी दिखाई पड़ी।

(2) विमुद्रीकरण देश की अर्थव्यवस्था में अचानक से आये एक भूकम्प की तरह था जिसने अर्थव्यवस्था में कुछ समय के लिये सुस्ती ला दी, इस सुस्ती के कारण देश का सकल घरेलू उत्पाद ळक्च् प्रभावित होता है।

(3) उत्सव के प्रबंधन में या शादी के प्रबंधन में नगदी की कमी के कारण कई समस्याएं आती है। अर्थात लोग उतनी धूमधाम से शादियां नही कर पाए जिस स्तर पर उन्होंने करने की सोची थी।

(4) लोगो को 500 एवं 1000 के नोट बदलवाने के लिये सुबह से शाम तक बैको के बाहर लाइन में खड़ा होना पड़ा जिसके कारण उनके व्यवसाय एवं काम धंधे पर बहुत असर पड़ा।

निष्कर्षः–

भारत सरकार के द्वारा जब विमुद्रीकरण की घोषणा की गई तो प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में विमुद्रीकरण के निर्णय को काले धन के विरूद्ध युद्ध की तरह बताया और उन्होने देशवासियों को इस बात का भरोसा दिलाया कि कुछ दिनों तक लोगों को परेशानी जरूर होगी पर यह निर्णय देश में काले धन की कमर तोड़ देगा। निर्णय के तत्काल बाद देश मे जगह – जगह सरकारी एजेसियों के छापे पड़ने प्रारंभ हो गया परिणाम कालाधन पकड़ा जाने लगा, बड़े पैमाने पर बैकों के पास नगदी आ गई, इस नगदी प्राप्ति का परिणाम यह हुआ कि बैको में ब्याज दर धटा कर ऋण लेना सस्ता कर दिया देशवासियों को व्यवसाय करने के लिये और घर बनाने के लिय सस्ती दरों पर कर्ज उपलब्ध होने लगा। सारांश के तौर पर यह कहा जा सकता है कि विमुद्रीकरण किसी भी देश क अर्थव्यवस्था के लिये लम्बे समय का फायदा लेकर आता है इसका कोई नही है विशेष नकारात्मक प्रभाव राष्ट्र पर नही पड़ता। इसके कुछ साइड इफेक्ट होते जरूर है परन्तु वह अल्पकालीन होते है दीर्घकाल में विमुद्रीकरण देश को आर्थिक सुदृढता प्रदान करते है।

निष्कर्ष के तौर पर ही कहा जा सकता है कि विमुद्रीकरण से नुकसान कम, फायदा अधिक हुआ है सरकार का यह निर्णय देश के लिये लाभकारी हो सकता है।

LBP PUBLICATION